



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124853

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

अपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 18097 वर्ष 2026

सचिनआवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: संजीव कुमार, शिव कुमार गुप्ता

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री संजीव कुमार व श्री शिव कुमार गुप्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अमित कुमार दुबे को सुना गया तथा रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना अनूपशहर, जिला बुलंदशहर से संबंधित वाद अपराध संख्या- 484 वर्ष 2025, अतर्गत धारा 111, 310(2), 317(3) बी.एन.एस. एवं धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है, यद्यपि उनके विरुद्ध कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी और विवेचना के दौरान लगभग 13 दिनों के बाद आवेदक का नाम सामने आया है और उसे गिरफ्तार कर उसके पास से 80,000/- रुपये की बरामदगी दिखाई गई है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि कोई शिनाख्त कार्यवाही आयोजित नहीं की गई है और इस मामले में आरोप पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का मातृ मामलों का अपराधिक इतिहास है और वह उन सभी सात मामलों में जमानत पर है तथा आवेदक दिनांक 31.12.2025 से जेल में निरुद्ध है, यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।
4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है और उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के कब्जे से 80,000/- रुपये बरामद किए गए हैं।
5. प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कराई गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने प्रथम सूचनादाता के घर में प्रवेश किया और उसे घर के अंदर बंद कर दिया तथा घर में रखे घरेलू सामान को लूट लिया और विवेचना के दौरान लगभग 13 दिनों के बाद आवेदक का नाम सामने आया और आवेदक के कब्जे से 80,000/- रुपये बरामद किए जाने की बात कही गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि कोई शिनाख्त कार्यवाही आयोजित नहीं की गई है और इस मामले में आरोप पत्र पहले

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



ही दाखिल किया जा चुका है। यह कहा गया है कि आवेदक का सात मामलों का आपराधिक इतिहास है और वह सभी सात मामलों में जमानत पर है तथा दिनांक 31.12.2025 से जेल में बंद है, यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

6. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ व विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को संज्ञान में लेते हुए, साथ ही जमानत देने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कपिल वधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 में पारित निर्णय के अधिदेश और इस न्यायालय द्वारा माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765 के मामले में दिए गए दिशानिर्देशों पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक- सचिन को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभुओं को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/विवेचना में निष्ठापूर्वक सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध को कारित करने में शामिल नहीं होगा।

(iv) आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभुओं की पहचान, स्थिति और निवास के प्रमाण का सत्यापन किया जाए। आवेदक के साथ-साथ प्रतिभुओं के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

11. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।

12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021, (2024) 10 एससी 685 जो 31.01.2023 को निर्णीत हुआ, के मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में इस आदेश की एक प्रति कारागार अधीक्षक, बुलंदशहर के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल द्वारा 24 घंटे के भीतर आवेदक को भेजी जाए।

(माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3 जून, 2026

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"